नवभारत टाइम्स 20 SEP 2018

PIB MUMBAI

PRESS INFORMATION BUREAU LIBRARY MUMBAI

'राज्य की आर्थिक सेहत ठीक, कंजूसी की जरूरत नहीं'

महाराष्ट्र को वित्त आयोग की नसीहत

Rajkumar.Singh
@Timesgroup.com

■ मुंबई : 15वें वित्त आयोग ने महाराष्ट्र को नसीहत दी है कि राज्य की अर्थव्यवस्था ठीक है, इसलिए वह कंजूसी न करे। राज्य के दौरे पर आए आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने कहा कि दूसरे राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था मजबूत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और कर्ज लेकर बड़ी परियोजनाओं को साकार कर सकती है।

सिंह ने पत्रकारों से कहा, 'महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। राज्य सरकार की तरफ से हमें क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए प्रस्ताव दिए गए हैं। ये प्रस्ताव विदर्भ और मराठवाडा के लिए हैं। इसके लिए धन की जरूरत होगी।'

मुंबई के लिए मांगे ₹ 50,000 करोड़

मुंबई के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपये और मराठवाडा-विदर्भ के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज देने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने आयोग को बताया कि देश की कुल जीडीपी में महाराष्ट्र का

15 प्रतिशत हिस्सा है और कुल विदेशी निवेश का 31 प्रतिशत महाराष्ट्र में आता है। मुंबई का विकास होगा, तो देश की विकास दर एक फीसदी बढ़ेगी। इससे 2025 तक देश की अर्थ व्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर पार कर जाएगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। यह तब होगा, जब महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगी।

'मुंबई पर आयोग का खास ध्यान'

मुंबई को विशेष पैकेज देने के बारे में आयोग के अध्यक्ष सिंह ने कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था की जान मुंबई है। मुंबई पर जनसंख्या का काफी बोझ है। राज्य सरकार ने मुंबई की बुनियादी सेवाओं विकास के लिए कई प्रस्ताव हमें दिए हैं। हम इन पर विचार करेंगे।'

नव भारत

20 SEP 2018

PIB MUMBAI

INFORMATION BUREAU LIBRARY ★ PRESS (MUMBAI)

मुंबई के लिए 50,000 करोड़

कार्यालय संवाददाता

मुंबई. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के विकास के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 15 वें वित्त आयोग से 50 हजार करोड़ रूपए के विशेष पैकेज की मांग की है. सीएम ने कहा कि मुंबई का विकास होगा तो देश की विकास दर में 1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी. इससे वर्ष 2025 तक देश की अर्थ व्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर पार कर जाएगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है.

वित्त आयोग से सीएम ने की मांग

बैठक कर सभी से ली राय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए 15वें वित्त आयोग का गठन किया है. इसका कार्यकाल 2020-25 तक होगा. आयोग देश के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहा. महाराष्ट्र नौंवा राज्य है , जहां आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह व आयोग के सदस्य शक्तिकांता दास, डॉ. अनूप सिंह, डॉ. अशोक लाहिरी, डॉ. रमेश चंद, सचिव अरविंद मेहता आए हैं. मंगलवार को आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों और उद्योग-व्यापार जगत के लोगों के साथ बैठक कर उनकी राय जानी. बुधवार को राज्य के वित्त विभाग ने राज्य की आर्थिक स्थिति और जरूरतों को लेकर आयोग के सामने प्रजेंटेशन दिया.

असंतुलन दूर करने पैसे की जरूरत

1 सीएम ने कहा कि यह तब होगा जब महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डालर तक पहुंचेगी. इसे देखते हुए ही मुंबई के लिए विशेष तौर से 50 हजार करोड़ रुपये की निधि मांग रहे हैं. सीएम ने कहा कि मुंबई में यातायात व्यवस्था सुचारू करने , इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने एवं कनेक्टिविटी के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है.

2 वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है. राज्य सरकार की तरफ से हमें क्षेत्रिय असंतुलन दूर करने के लिए प्रस्ताव दिए गए हैं. इसके लिए पैसे की जरूरत होगी. वित्त आयोग ने राज्य की आर्थिक मजबूती का हवाला देते हुए कहा कि विकास के लिए वित्त विभाग और अधिक कर्ज ले सकता है.

राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत

देश के अग्रणी राज्यों में शुमार महाराष्ट्र आर्थिक क्षेत्र में भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है. राज्य के दौरे पर आए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई और विदर्भ-मराठवाड़ा के लिए विशेष पैकेज की मांग की है. सीएम ने आयोग से मुंबई के विकास के लिए 50 हजार करोड़ रुपये और मराठवाडा-विदर्भ के लिए 25 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज देने की मांग की है.राज्य की तरफ से प्रजेंटेशन देते हुए सीएम ने आयोग को बताया कि देश की कुल जीडीपी में महाराष्ट्र का 15 प्रतिशत हिस्सा है.

सीएम की प्रमुख मांग

- मुंबई के लिए 50 हजार करोड़
- मराठवाडा-विदर्भ के लिए 25 हजार करोड़
- पर्यावरण के लिए 15 सौ करोड़
- विरासत संरक्षण के लिए 825 करोड़
- वनों के लिए 1,177 करोड़
- न्याय व्यवस्था के लिए 1700 सौ करोड़

मुंबई पर विशेष ध्यान

मुंबई भारतीय अर्थ व्यवस्था की जान है. मुंबई पर जनसंख्या का काफी बोझ है. राज्य सरकार ने मुंबई की बुनियादी सेवाओं विकास के लिए कई प्रस्ताव हमें दिए हैं.

एनके सिंह, वित्त आयोग के अध्यक्ष

दैनिक राष्ट्रभूमि

20 SEP 2018

PIB MUMBAI

PRESS INFORMATION BUREAU MUMBAI

१५वां वित्त आयोगः महाराष्ट्र ने मुंबई क्षेत्र के लिये ५० हजार करोड़ रु.की मांग की

मुंबई, पन्द्रहवें वित्त आयोग के साथ बैठक में महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को मुंबई शहर और मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) के लिए विशेष समर्थन के रूप में 50,000 करोड़ रुपये की मांग की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आयोग को दिये एक ज्ञापन में कहा कि मुंबई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमें मुंबई के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। हमें देश के जीडीपी में मुंबई के महत्व को स्वीकार करने की जरूरत है। मुंबई और एमएमआर (जिसमें आसपास की टाउनशिप शामिल हैं) के लिए 50,000 करोड़ रुपये की मांग करते हुए उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 32,327 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि 32,327 करोड़ रुपये में से, 25,000 करोड़ रुपये आर्थिक रूप से पिछड़े मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार के लिए जरूरी होगा। विशेष अनुदान की मांग में पर्यावरण प्रबंधन के लिए 1,400 करोड़ रुपये, पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण एवं सुरक्षा तथा आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए 200 करोड़ रुपये, नदियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए 1,000 करोड़ रुपये तथा तटीय जैव विविधता संरक्षण के लिए 200 करोड़ रुपये शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए 825 करोड़ रुपये, संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों के संरक्षण, मरम्मत और विकास के लिए 600 करोड़ रुपये, किलों के संरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपये और ऑडिटोरियम और सिनेमाघरों के उन्नयन के लिए 125 करोड़ रुपये की मांग की। राज्य सरकार ने अदालत भवनों के नवीनीकरण सहित न्यायिक प्रशासन को मजबूत करने के लिए 1,700 करोड़ रुपये की मांग की। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र देश का विकास इंजन है और इसलिए देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हमें अधिक हिस्सेदारी (कर राजस्व में) की जरूरत है।

हमारा महानगर
PIB MUMBAI
20 SEP 2018

PRESS INFORMATION BUREAU
MUMBAI

मुंबई के लिए 50 हजार करोड़ की मांग

महानगर संवाददाता

मुंबई

महाराष्ट्र की जरूरतों और राज्य के विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के समक्ष तर्क आधारित प्रजेनटेंशन करते हुए राज्य को नियमित रूप से मिलने वाले प्रावधान के अलावा मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र के विकास के लिए 50 हजार करोड़ तथा विदर्भ और मराठवाडा के संतुलित सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 25 हजार करोड़ रुपए की विशेष सहायता की मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र ने हमेशा देश के आर्थिक विकास में भारी योगदान दिया है। देश के सकल घरेलु आय में महाराष्ट्र का हिस्सा 15 फीसदी है। देश के कुल निर्यात में महाराष्ट्र का हिस्सा 20 फीसदी है। भारत

15वें वित्त आयोग के समक्ष प्रजेनटेंशन

आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में से 31 फीसदी निवेश महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक अधिक औद्योगीकरण हुआ है और ऐसे में मुंबई का विकास तेजी से हो रहा है। राज्य सरकार की तरफ से की गई सिफारिश केवल मुंबई या महाराष्ट्र के लिए नहीं, इससे भारत का विकास होगा। मुंबई महानगर प्रदेश का विकास होने से देश की अर्थव्यवस्था को एक फीसदी का योगदान मिलेगा। वर्ष 2025 तक भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। यह सपना तभी सच होगा, जब महाराष्ट्र की अर्थ व्यवस्था ट्रिलियन डॉलर की होगी। इसे ध्यान में रखते हुए वित्त आयोग मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) क्षेत्र के विकास के लिए 50 हजार करोड़ रुपए की विशेष सहायता प्रदान करें।

विशेष निधि मांग

मुख्यमंत्री ने आयोग के समक्ष अदालतों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1 हजार 700 करोड़, वन-वन्यजीव संरक्षण और राज्य में हरित क्षेत्र के विकास के लिए 1 हजार 177 करोड़, जैव विविधता संरक्षण, संवर्धन और समुद्री किनारों के संरक्षण के लिए 1 हजार 400 करोड़ और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण, गढ़-किलों की मरम्मत के लिए 825 करोड़ रुपए की मांग की।

केंद्रीय करों में मिले महाराष्ट्र को उचित हिस्सा

14वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 42 फीसदी है। 15वें वित्त आयोग से यह हिस्सा 50 फीसदी करने की सिफारिश राज्य सरकार की तरफ से की गई। जीएसटी कर प्रणाली से केंद्रीय कर का संकलन बड़े पैमाने पर बढ़ने की संभावना है। इसमें महाराष्ट्र का भारी योगदान है। ऐसे में केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 50 फीसदी करते हुए महाराष्ट्र के साथ उचित न्याय किया जाए। मुख्यमंत्री ने केंद्र पुरस्कृत योजनाओं में केंद्र और राज्य के हिस्से की फिर से व्याख्या करने की मांग की।

विदर्भ, मराठवाडा के लिए मांगें 25 हजार करोड़

मुख्यमंत्री *ने कहा कि राज्य के 36 जिलों में से 16 जिलों में प्रति व्यक्ति आय राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय की अपेक्षा कम है। इन 16 जिलों में से 14 जिलों में प्रति व्यक्ति आय औसतन राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की अपेक्षा कम है। राज्य की 351 तहसीलों में से 125 तहसीलों में मानव विकास निर्देशांक कम है। इसमें से अधिकांश तहसीलें मराठवाडा और विदर्भ की हैं। ऐसे में आयोग को दोनों विभागों के समान आर्थिक विकास के लिए 25 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।*

मुख्यमंत्री की भूमिका से आयोग सहमत

महाराष्ट्र की जरूरतों और राज्य के विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के समक्ष तर्क आधारित प्रजेनटेंशन पर वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने सकारात्मक भूमिका अपनाए जाने की बात कही है। उन्होंने मुख्यमंत्री की भूमिका महाराष्ट्र समृद्ध होगा तो देश का तेजी से विकास होगा पर सहमति प्रकट की। सिंह ने महाराष्ट्र के वृक्षारोपण और वित्तीय व्यवस्थापन के काम की सराहना की।

राज्य को आर्थिक शक्ति प्रदान करे वित्त आयोग : मुनगंटीवार

मुंबई। राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि वित्तीय दायित्व को पूरा करने वाले, आर्थिक नियम का पालन करने वाले और देश के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाले महाराष्ट्र को वित्त आयोग आर्थिक शक्ति प्रदान करें। उन्होंने विदर्भ और मराठवाड़ा के विकास का अनुशेष दूर करने के लिए 25 हजार करोड़ तथा मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 50 हजार करोड़ रुपए की मांग की। पुरानी अल्पबचत योजनाओं के 65 हजार 445 करोड़ रुपए के कर्ज पर आनेवाले ब्याज के बोझ से महाराष्ट्र को मुक्त करने और ओपन मार्केट के ब्याज दर के अनुसार इस कर्ज के ब्याज की पुनर्रचना की जाने की महत्वपूर्ण मांग भी उन्होंने की।

राज्य आर्थिक दृष्टि से सक्षम

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य आर्थिक दृष्टि से सक्षम है। उन्होंने कहा कि वस्तु और सेवा टैक्स प्रणाली के अमल के बाद राज्य ने डेढ़ साल में ही अपनी आय बढ़ाकर सक्षमता हासिल की है, जिसकी सराहना जीएसटी परिषद ने भी की है। इस साल के आय में अब तक 23 फीसदी से बढ़ोतरी हुई है। राज्य के टैक्स धारकों के पंजीयन में प्रतिमाह 30 हजार से बढ़ोतरी हुई है।यह संख्या अबतक 7.5 लाख से बढ़कर 14 लाख तक है।सकल राज्य की आय से राज्य के कर्ज का प्रमाण 2005-06 के 25.5 फीसदी से कम होकर वर्ष 2017-18 में 16.1 फीसदी हुआ है।इसकी वित्तीय दर (2009-10) के 3.1 से (2017-18) में 1 फीसदी तक कम करने में राज्य सफल रहा है। राजस्व आय की तुलना में ब्याज का प्रमाण 22 फीसदी से कम होकर यह 2018-19 के बजट अनुमान के अनुसार 12 फीसदी होना अपेक्षित है। सह्याद्री अतिथि गृह में हुई बैठक में वित्त आयोग के सदस्य शक्तिकांता दास डॉ. अशोक लहरी, डॉ. अनूप सिंह, रमेश चंद, सचिव अरविंद मेहता अन्य पदाधिकारियों के साथ राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल, कामगार मंत्री संभाजी पाटिल-निलंगेकर, जलसंधारण मंत्री राम शिंदे, वित्त राज्य मंत्री दीपक केसरकर वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव यूपीएस मदान, नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती के साथ सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुंबई भारतीय इकोनॉमी का इंजिन : वित्त आयोग

मुंबई। भारत सरकार के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि मुंबई भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन है। महाराष्ट्र खराब आर्थिक स्थिति की खबरों को भ्रामक बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के आर्थिक हालात देश से अच्छे हैं। वे सह्याद्रि गेस्ट हाऊस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान आयोग के सदस्य शक्तिकांता दास, डॉ. अनुप सिंह, डॉ. अशोक लाहिरी, डॉ. रमेश चंद, सचिव अरविंद मेहता भी मौजूद थे। केंद्र सरकार द्वारा गठित 15वां वित्त आयोग महाराष्ट्र दौरे पर आया था। मंगलवार को आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों और उद्योग-व्यापार जगत के लोगों के साथ बैठक कर उनकी राय जानी। बुधवार को वित्त आयोग के समक्ष महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति और जरूरतों को लेकर प्रजेंनटेशन दिया गया। सिंह ने कहा कि आयोग के निष्कर्षों के आधार पर महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति को लेकर जो बाते कही जा रही हैं, वे सही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम आंकड़ों को बनाने-बिगाड़ने का काम नहीं करते पर इन आंकडों का गलत विश्लेषण किया गया है। इसको लेकर भ्रामक खबरें प्रकाशित हुई हैं। सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से हमें महाराष्ट्र का क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए प्रस्ताव सौंपे गए हैं। इस कार्य के लिए निधि की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि मुंबई भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन है। मुंबई पर जनसंख्या का काफी भार है। यहां इंफ्रास्टेक्चर के विकास के लिए कई प्रस्ताव हमें दिए गए हैं। एक सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि माइग्रेशन देशव्यापी समस्या है। हम केरल गए थे, वहां के लोग रोजी-रोटी के लिए विदेशों में चले गए हैं। इसलिए वहां दूसरे राज्यों से आए लोग काम कर रहे हैं।

आज का आनंद
PIB MUMBAI
20 SEP 2018

महाराष्ट्र के विकास हेतु 80 हजार करोड़ रुपए दें

15 वें वित्त आयोग की बैठक में सीएम ने मांग की : आयोग के अध्यक्ष ने राज्य के ड्राफ्ट को सराहा

- सीएम ने कहा- विदेशी निवेश में महाराष्ट्र अव्वल
- निर्यात में भी राज्य का महत्वपूर्ण योगदान
- टैक्स मामले में राज्य के योगदान के अनुसार फंड मिलना चाहिए

मुंबई, 19 सितंबर (वि.प्र.)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एन.के. सिंह के साथ बैठक की. इस अवसर पर वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार तथा गृह राज्यमंत्री दीपक केसकर उपस्थित थे. मुख्यमंत्री ने यहां राज्य के विकास हेतु 80 हजार करोड़ रुपए मांगे.

मुख्यमंत्री ने बैठक में भारतीय अर्थव्यवस्था में महाराष्ट्र के योगदान के विषय में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में महाराष्ट्र अग्रणी प्रदेश है. इसके अलावा निर्यात के मामले में भी महाराष्ट्र का योगदान सबसे ज्यादा है. सीएम फडणवीस ने वृक्षारोपण के क्षेत्र में महाराष्ट्र के कार्यों के लिए इंसेंटिव की मांग की. उन्होंने विदर्भ तथा मराठवाड़ा के विकास हेतु 25000 करोड़ रुपए तथा मुंबई के लिए 50 हजार करोड़ रुपए की मांग की. इसके अलावा पर्यावरण व्यवस्थापन के लिए अलग से 1400 करोड़ रुपए देने की मांग की. प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण तथा हरित क्षेत्र के विकास हेतु 1177 करोड़ तथा न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 1700 करोड़ रुपए मांगे हैं. चौदहवें वित्त आयोग के मुताबिक केंद्र के टैक्स में महाराष्ट्र का हिस्सा 42% है.

(शेष पेज 2 पर)

DNA
PIB MUMBAI
20 SEP 2018

CM highlights slowdown in industrial growth, low capex

Fadnavis hopes state to be a trillion dollar economy with higher central funds in near future

Sanjay Jog
sanjay.jog@dnaindia.net

Even though Maharashtra is a premier state in terms of gross state domestic product (GSDP), it continues to face four major challenges — rain-fed agriculture compounded by climate change, balanced regional development, fast-growing urbanization and management of increasing revenue deficit. Besides, there has been a slow down in industrial growth between 2015-16 and 2017-18 due to dip in mining and quarry sector, electricity, gas, water supply, and other utility services.

The share of capital expenditure has almost halved to 11 per cent in 2018-19 from 24 per cent in 2008-09 because of substantial grants made available to urban local bodies and panchayati raj institutions. Even though this expenditure is reflected in the state government's accounts as revenue expenditure, it does not result in the creation of capital assets in Maharashtra.

Apart from this, the share of total receipts compared to gross state domestic product (GSDP) has been on a declining trend and it has come down to 12.3 per cent in 2017-18 from 14.9 per cent in 2005-06. The growth in receipts has not kept pace with the economic growth of the state because the tax on services was under the ambit of the central government.

These concerns were highlighted by the state chief minister Devendra Fadnavis in his presentation to the 15th Finance Commission (FC) headed by former revenue secretary NK Singh.

Fadnavis however, hoped that the state government will be in a position to turn around with increased allocation of resources from the FC and a slew of steps taken by it to deal with the situation. "With the increased support from the central government, the state will be able to achieve trillion dollar economy assuming a growth of 12 per cent in gross state domestic product by 2024-25," he noted.

Fadnavis further stated that the FC needs to give weight to new parameters like urbanization, fiscal efficiency, and green cover while devoluting funds. "The changing economic and population profile of Maharashtra needs to be appropriately factored in any pattern of devolution. The state will have to be incentivised adhering to the generally accepted fiscal deficit norm," he said.

Fadnavis insisted that Maharashtra needs to be incentivised for taking steps in increasing tree cover, especially in non-forested lands. "The government has proposed weightage of 2.5 per cent for this purpose," he noted.

Chief Minister said Maharashtra has a skewed with Mumbai's per capita income distorting the average per capita income of the state and as a result, the state has received lesser funds. "The government has urged the FC to cut the abnormally high weightage given to the income distance criteria by the earlier FCs. The government has proposed weightage of not more than 15 per cent for this criterion in its current form.

15th Finance Commission chairman NK Singh addresses the media regarding their visit to Mumbai on Wednesday —PTI

SHARP DECLINE

- There has been a slow down in industrial growth between 2015-16 and 2017-18 due to dip in mining and quarry sector, electricity, gas, water supply, and other utility services.
- **The share of capital expenditure has almost halved to 11 per cent in 2018-19 from 24 per cent in 2008-09 because of substantial grants made available to urban local bodies and panchayati raj institutions**

Maha outplays Guj in revenue receipt growth

DNA Correspondent
correspondent@dnaindia.net

Fifteenth Finance Commission chairman NK Singh on Wednesday showered praise on Maharashtra government for higher revenue receipts compared Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu. Singh after his meeting with chief minister Devendra Fadnavis said that state's parameters with regard to revenue and fiscal deficits and debt to gross state domestic product (GSDP) are well within the limit laid down by the 14th Finance Commission and Fiscal Responsibility and Budget Management Act. He, however, stressed that the state government will need to step up its efforts to increase capital expenditure for the creation of assets.

Singh told reporters that Maharashtra's revenue receipts have fallen to 11.05 per cent in 2014-17 from 17.69 per cent in 2009-13. "This is not Maharashtra specific. Its own revenue receipts in 2017-18 have in fact increased by 13.80 per cent and own tax revenue by 13.40 per cent. The all-India average with regard to revenue receipts fell to 10.6 per cent from 15.4 per cent. While in Gujarat it came down to 4.3 per cent from 26.3 per cent, in Karnataka saw a decline from 20.7 per cent to 9 per cent in the same period. However, in the case of Tamil Nadu the fall was quite sharp at 5.2 per cent from 24.9 per cent," he noted.

Singh's clarification came on a press release issued by the Press Information of Bureau (PIB) on its behalf last Saturday. According to the press release, the state's revenue receipts and own tax revenue have fallen and the percentage of capital expenditure to total expenditure has remained between 11 and 12 during 2013-17.

Full report on dnaindia.com

The Indian EXPRESS

20 SEP 2018

PIB MUMBAI

Maharashtra wants 50 per cent share for states in central taxes

SANDEEP ASHAR
MUMBAI, SEPTEMBER 19

MAHARASHTRA ON Wednesday demanded a higher share for states from the divisible pool of central tax collections. In an official memorandum submitted to the Fifteenth Finance Commission, the BJP government in the state claimed that an increased central devolution, or a 50 per cent share, would reduce the pressure on the state's finances and the revenue deficit.

Based on recommendations of the previous commission, the Narendra Modi government had earlier increased the share of states in central tax collections to 42 per cent from the previous level of 32 per cent. But Maharashtra on Wednesday argued that the net gain to it due to the move was "immediately offset by a sharp change in the centre: state sharing formula in centrally sponsored schemes and the Centre's discontinuance of funds for some such schemes". The commission's chairman N K Singh revealed that other states they visited also raised a similar demand.

Contending further that the proportion of surcharges and cess levied by the Centre had increased substantially since 2015-16 and that these now form a sizeable part of the taxes, Maharashtra has also demanded that "these should also be a part of the divisible pool". It has further demanded that states should also be given proportionate share of the additional funds generated through cesses and surcharges, spectrum sales, license fees, and disinvestments, among other revenues.

While the Maharashtra government has announced a goal to become a $ 1 trillion economy by 2025, it has now sought funds totalling Rs 80,102 crore from the Centre to achieve the target. "Based on current trends, we'll reach a GSDP level of Rs 55.2 lakh crore by 2024-25 assuming a 12 per cent growth for the period. But as a premier state, we'd like to increase our contribution to the national GDP and have taken many crucial initiatives to help the economy at a much faster clip in the 2020-25 period. But we need more fiscal space to sustain and increase this speed," the state's memorandum states.

While the 14th Finance Commission had shot down the state's requests for state specific and sectoral special grants, Maharashtra on Wednesday sought a Rs 25,000 crore special grant for "reducing the development deficit in the backward regions of Vidarbha and Marathwada".Underlining the importance of the Mumbai metropolis as the country's economic powerhouse, it further demanded Rs 50,000 crore for infrastructure growth in the region.

Chief Minister Devendra Fadnavis said, "Mumbai is the backbone of our economy. We must strengthen the infrastructure in Mumbai. We need to acknowlegde Mumbai's importance to the nation's GDP, and Maharashtra's contribution as the country's growth engine."

Apart from this, Maharashtra has sought grants for improving judicial infrastructure (Rs 1700 crore), forest/wildlife and green cover (Rs 1177 cr), environment conservation and management (Rs 1400 cr), and preservation of cultural heritage (Rs 825 cr).

Singh later said, "The commission shares Maharashtra's aspiration to become a trillion dollar economy. We believe that the state has seen sharp progress in the last few years."

Meanwhile, reiterating its demand that performing states should not be penalised but rewarded, the government sought a revision in formula for tax devolution among the states.

"We feel that disproportionate emphasis has been given to equity parameters at the cost of parameters that reward efficiency, and hold a strong view that the Commission should give due weightage to both equity and efficiency parameters."

Maharashtra has said that the income distance criteria's weightage should be lowered from the current 50 per cent to 15 per cent, while suggesting that the deprivation index of states as per the latest Socio Economic and Caste Census (15 per cent) and the level of urbanisation (10 per cent) should also be considered. It has agreed that the 2011 population census be considered, while arguing that fiscal efficiency (7.5 per cent) and tree cover (2.5per cent) should also be assessment parameters.

hindustan times
20 SEP 2018
PIB MUMBAI

Finance panel says Maha not spending enough on devpt; CM asks for ₹81-K cr

CAPITAL EXPENDITURE 1% OF GDP Govt seeks ₹50K-cr for city; panel suggests borrowing to create assets

Faisal Malik
faisal.malik@hindustantimes.com

CM Devendra Fadnavis with members of the 15th Finance Commission on Wednesday. HT PHOTO

MUMBAI: Even as the 15th Finance Commission of India expressed concern over the state's capital expenditure against the total annual spending, the government on Wednesday demanded more than ₹81,000 crore as special grant from the commission, including ₹50,000 crore for Mumbai, ₹25,000 crore for Vidarbha and Marathwada and ₹5,000 crore for thematic schemes. Besides, the state has also asked to increase devolution of funds to 50% from 42%.

Capital expenditure generally means the state's spending on development works. Currently, the capital expenditure of the state is just 1% of the gross domestic product (GDP). The commission has suggested it be increased by borrowing more money to create more capital assets.

"In the meeting with the commission on Wednesday, chief minister Devendra Fadnavis said the state can achieve one-trillion-dollar economy by 2024-25, only if it gets enough financial support from Centre and going by the current method, it will reach only the 50% mark," said a senior official from state finance department, privy to the development.

"Maharashtra must be credited as one of those states where the fiscal deficit is well within the 3% target laid down by Fiscal Responsibility and Budgetary Management Act (FRBM). In relation to the debt to GDP, Maharashtra is well within the fiscal parameters. It means, it has fiscal space left for capital expenditure, which we encourage the state to look for, bringing a balancing between capital and revenue expenditure," said NK Singh, chairman of the commission.

"We were promised that if we look at the capital expenditure made by many parastatals (government undertakings), the capital expenditure figures are increasing. The performance of the state government on key macro targets of fiscal deficit, primary deficit and debt to GDP is very laudable one," he said.

UPS Madan, additional chief secretary, finance department, said, "The state has consciously kept capital expenditure of the government undertakings separate from the state's budget by adopting a system where they will invest in urban infrastructure and state's capital expenditure will be used for the rest of the state. By adding capital expenditure of both, it will reach up to 2% of GDP."

The fresh observations of the commission have come days after it said the state growth rate and revenue receipts are falling, which created a flutter. The commission pointed out the growth rate of state's revenue had fallen to 11.05% in 2014-17 from 17.69% from 2009-13. It also said the state's tax revenue declined to 8.16% in 2014-17 from 19.44% in 2009-13.

"The finance commission doesn't manipulate the figures. The figures in the press release came from a recent report of the Account General of Maharashtra. The financial picture is somewhat misleading, as the selection done by the Account General of Maharashtra for the fiscal years is sporadic. If you compare the revenue situation of Maharashtra with other states, it is much better," Singh said.

The finance commission chairman said the state's demand for special grants for Mumbai will be considered and it will be reflected in its final recommendations.

In its 70-page memorandum, the state said the states should also be given proportionate share of the additional funds generated through cesses and surcharges, spectrum, sales, licenses fees, disinvestment etc.

"For devolution of taxes among states, we hold a strong view that the finance commission should give due weightage to both equity and efficiency parameters. In the past, disproportionate emphasis has been given to the equity parameters at the cost of other relevant parameters that rewards efficiency. This now wants correction," said the memorandum.

The state has suggested a new formula for giving weightage for sharing devolution of funds. It has sought 35% weightage on population (2011 census), 15% on area, 15% on income distance, 10% on urbanisation, 7.5% on fiscal efficiency, 2.5% on tree cover and the rest on deprivation of families in rural areas, which should be based on socio-economic caste census report.

PIB MUMBAI

20 SEP 2018

Maharashtra Times	In Review, States Economic Situation is Sound Maharashtra is a growth Centre of Nation

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

महाराष्ट्राच्या प्रगतिपुस्तकावर लाल शेरा मारणाऱ्या वित्त आयोगाचे घुमजाव

'पुनर्मूल्यांकना'त राज्याची आर्थिक स्थिती 'उत्तीर्ण'

दोन दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्राच्या आर्थिक व्यवस्थेबाबत चिंतेचा सूर काढणाऱ्या वित्त आयोगाने बुधवारी महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती उत्तम असून, राज्याची प्रगती सुरू असल्याचे प्रशस्तिपत्रक दिले आहे. कर्नाटक, गुजरात आणि तमिळनाडूपेक्षाही महाराष्ट्र आर्थिक स्थितीत अग्रेसर असल्याचे सांगत वित्त आयोगाने आपल्या आधीच्याच निष्कर्षांवरून घुमजाव केले.

महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीबाबत दोन दिवसांपूर्वीच वित्त आयोगाने चिंता व्यक्त केली होती. गेले दोन दिवस वित्त आयोगाचे पथक महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहे. या पथकाची सरकारच्या वतीने चांगली बडदास्त ठेवण्यात आली होती. वित्त आयोगाच्या सदस्यांनी राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व नगरपालिकेच्या विविध प्रतिनिधींशीही तीन दिवसांच्या दौऱ्यात चर्चा केली. आयोगाच्या सदस्यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्य शासनातील विविध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

खापर 'पीआयबी'वर!

वित्त आयोगाने दोन दिवसांपूर्वी आर्थिक स्थितीबाबत व्यक्त केलेल्या चिंतेबाबतचे खापर केंद्र सरकारच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोवर (पीआयबी) फोडले. वित्त आयोगाने महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केलेली नाही, असेही स्पष्टीकरणही बुधवारी आयोगाने दिले.

त्यानंतर बुधवारी वित्त आयोगाच्या पथकाने पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये सदस्यांनी महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीची तोंड भरून स्तुती केली. 'मुंबई हे महाराष्ट्राबरोबरच देशाच्या आर्थिक विकासाचे केंद्र आहे. राज्याने मानव विकास निर्देशांकातही चांगली प्रगती केली आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा विकासदर वाढता आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था चांगली आहे. देशात सर्वाधिक पायाभूत सुविधांची कामे महाराष्ट्रात सुरू आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा आहे. गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र आर्थिक स्थितीत तसेच प्रगतीत पुढे आहे', असे कौतुकोद्गार वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह यांनी काढले. 'वस्तू व सेवा कराच्या वसुलीमध्ये राज्य आघाडीवर आहे. विभागीय असमतोल कमी करण्यासाठी, राज्याची प्रगती होण्यासाठी वित्त आयोग सूत्र ठरवणार आहे', असेही त्यांनी नमूद केले.

➤ देशाचे ग्रोथ सेंटर...६

दिनांक १६ सप्टेंबर

महसुली उत्पन्न घसरले आहे. करांद्वारे मिळणारे उत्पन्नही कमी झाले आहे. एकूण खर्चांपैकी भांडवली खर्चाचे प्रमाणही किरकोळ आहे.

दिनांक १९ सप्टेंबर

मानव विकास निर्देशांकात महाराष्ट्राची प्रगती. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा विकासदर वाढता. राज्याची अर्थव्यवस्था चांगली आहे.

महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ सेंटर

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

महाराष्ट्राच्या आर्थिक व्यवस्थेबाबत चिंतेचा सूर काढणाऱ्या वित्त आयोगाने बुधवारी महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती उत्तम असल्याचा निर्वाळा दिला. 'महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ इंजिन आहे. एक लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेचे ध्येय गाठण्यासाठी राज्य शासनाने सविस्तर प्रस्ताव दिले आहेत', अशी माहिती पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह यांनी या पत्रकार परिषदेत दिली.

पत्रकार परिषदेस वित्त आयोगाचे सदस्य शक्तीकांता दास, डॉ. अनुप सिंग, डॉ. अशोक लाहिरी, डॉ. रमेश चंद, सचिव अरविंद मेहता आदी उपस्थित होते. यावेळी एन. के. सिंह म्हणाले, 'मुंबईत येण्यापूर्वी आयोगाने पुण्यात अर्थतज्ज्ञांसोबत चर्चा केली असून, त्यांच्या सूचनांचा समावेश आयोग आपल्या अहवालात करणार आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाने राज्याच्या आर्थिक व पायाभूत सुविधांच्या प्रगतीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आयोगासमोर मांडले असून, त्याचा आयोग सकारात्मकदृष्ट्या विचार करेल. इतर राज्यांतून येणाऱ्या नागरिकांचा प्रश्न महाराष्ट्र व विशेषतः मुंबईसाठी महत्त्वाचा असून, त्यामुळे पायाभूत सुविधांवर मोठा भार पडतो. स्थलांतरितांच्या या समस्येवरही आयोग विचार करणार आहे.'

विदर्भ, मराठवाड्याबाबत चिंता

मराठवाडा आणि विदर्भाचा संतुलित विकास झालेला नाही. त्यामुळे य[...] मागासलेल्या भागाकडे विशेष लक्ष द्याव[...] लागणार आहे. तशी शिफारस आयो[...] केंद्र सरकारकडे करणार असल्याचे[...] आयोगाने स्पष्ट केले.

कर्जमाफीचा परिणाम नाही...

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना राज[...] सरकारने कर्जमाफी दिली आहे. पर[...] या कर्जमाफीमुळे राज्याच्या आर्थि[...] स्थितीवर कोणताही परिणाम झाले[...] नाही, असे वित्त आयोगाने म्हटले आ[...]

महाराष्ट्र टाइम्स
PIB MUMBAI
20 SEP 2018

'मुंबईसाठी ५० हजार कोटी द्या'

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

मुंबई महानगर प्रदेशचा विकास झाल्यास देशाची अर्थव्यवस्था आणखी एक टक्क्याने विकसित होईल. सन २०२५पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरची करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था लाख कोटी डॉलरने विकसित होईल तेव्हाच पंतप्रधानांचे हे स्वप्न साकार होईल हे लक्षात घेऊन मुंबई महानगर क्षेत्राच्या विकासासाठी ५० हजार कोटी रुपयांचे विशेष सहाय्य द्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी पंधराव्या वित्त आयोगाकडे केली.

चौदाव्या वित्त आयोगानुसार केंद्रीय करातील राज्यांचा हिस्सा ४२ टक्के आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाने हा हिस्सा ५० टक्के इतका करावा. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे (जीएसटी) केंद्रीय कर संकलनात मोठ्या प्रमाणात वाढ अपेक्षित आहे. कर संकलनात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे केंद्रीय करात महाराष्ट्राला न्याय हिस्सा मिळावा, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली. निःपक्षपातीपणे निधीचे वाटप या सूत्रानुसार आयोगाने राज्यांची कार्यक्षमता आणि निधीचा प्रभावीपणे वापर करण्याची क्षमता विचारात घ्यावी, असेही फडणवीस यांनी सुचविले.

देवेंद्र फडणवीस यांनी पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग आणि आयोगाच्या सदस्यांसमोर महाराष्ट्राच्या गरजा आणि विकासाची क्षेत्रे यासंदर्भात सादरीकरण केले. यावेळी नियमित स्वरूपात मिळणाऱ्या निधी व्यतिरिक्त मुंबई तसेच विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी विशेष निधी देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक औद्योगिकरण झालेले राज्य असून मुंबईचा विकास झपाट्याने होत आहे. राज्य सरकार करत असलेल्या शिफारशी या केवळ मुंबई किंवा महाराष्ट्रासाठी नसून भारताच्या विकासासाठी असल्याचे फडणवीस यांनी आयोगाला सांगितले.

राज्याच्या ३५१ तालुक्यांपैकी १२५ तालुके हे मानव विकास निर्देशांकात मागे आहेत. त्यातील बरेच तालुके हे मराठवाडा आणि विदर्भातील आहेत. सामाजिक समतोल तसेच आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी या दोन विभागांच्या विकासाला केंद्राने घटनेच्या कलम ३७१ (२) अन्वये प्रधान्य दिले आहे. त्यामुळे आयोगाने मराठवाडा आणि विदर्भाच्या आर्थिक विकासासाठी २५ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करावे, असा आग्रह फडणवीस यांनी धरला.

Maharashtra Times	Give Rs. 50 thousand cr.

सकाळ

20 SEP 2018

PIB MUMBAI

मुंबई परिसराच्या विकासासाठी हवेत ५० हजार कोटी

वित्त आयोगाकडे राज्याची मागणी

सकाळ न्यूज नेटवर्क

मुंबई, ता. १९ : राज्याच्या गरजा आणि राज्याची विकास क्षेत्रे याबाबत पंधराव्या वित्त आयोगासमोर सादरीकरण करताना सरकारने राज्याला नियमित स्वरूपात प्राप्त होणाऱ्या तरतुदींव्यतिरिक्त मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राच्या (एमएमआर) विकासासाठी ५० हजार कोटी तर विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या समतोल सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी २५ हजार कोटी रुपयांच्या विशेष साह्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

राज्याने नेहमीच देशाच्या आर्थिक विकासात भरीव योगदान दिल्याचे सांगून ते म्हणाले, "सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा हिस्सा १५ टक्के, तर देशाच्या एकूण निर्यातीत महाराष्ट्राचा हिस्सा २० टक्के आहे. भारतात येणाऱ्या थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी ३१ टक्के गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात येते. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक औद्योगीकरण झालेले पान ४ वर »

लोंढ्यांमुळे मुंबईला विशेष मदत

मुंबईत परप्रांतियांच्या अविरत लोंढ्यांमुळे निर्माण झालेल्या समस्या, अडचणींची अधिकृत दखल १५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह यांनी बुधवारी मुंबई दौऱ्यात घेतली. या लोंढ्यांमुळे पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण लक्षात घेता मुंबईसाठी केंद्राच्या योजनांतून विशेष मदत देण्याचा विचार करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती इतर राज्यांच्या तुलनेत उत्तम व समाधानकारक आहे. आर्थिक शिस्तीत महाराष्ट्राचा आदर्श इतर राज्यांनी घ्यायला हवा, असे प्रशस्तिपत्रकही त्यांनी दिले.

Sakal	Need more 50 Thousand Cr. for Mumbai's Infrastructure Development – State asked to the Finance Commission

सकाळ

20 SEP 2018

PIB MUMBAI

मुंबई परिसराच्या विकासासाठी हवेत ५० हजार कोटी

वित्त आयोगाकडे राज्याची मागणी

सकाळ न्यूज नेटवर्क

मुंबई, ता. १९ : राज्याच्या गरजा आणि राज्याची विकास क्षेत्रे याबाबत पंधराव्या वित्त आयोगासमोर सादरीकरण करताना सरकारने राज्याला नियमित स्वरूपात प्राप्त होणाऱ्या तरतुदींव्यतिरिक्त मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राच्या (एमएमआर) विकासासाठी ५० हजार कोटी तर विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या समतोल सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी २५ हजार कोटी रुपयांच्या विशेष साह्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

राज्याने नेहमीच देशाच्या आर्थिक विकासात भरीव योगदान दिल्याचे सांगून ते म्हणाले, "सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा हिस्सा १५ टक्के, तर देशाच्या एकूण निर्यातीत महाराष्ट्राचा हिस्सा २० टक्के आहे. भारतात येणाऱ्या थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी ३१ टक्के गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात येते. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक औद्योगीकरण झालेले पान ४ वर »

लोंढ्यांमुळे मुंबईला विशेष मदत

मुंबईत परप्रांतियांच्या अविरत लोंढ्यांमुळे निर्माण झालेल्या समस्या, अडचणींची अधिकृत दखल १५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह यांनी बुधवारी मुंबई दौऱ्यात घेतली. या लोंढ्यांमुळे पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण लक्षात घेता मुंबईसाठी केंद्राच्या योजनांतून विशेष मदत देण्याचा विचार करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती इतर राज्यांच्या तुलनेत उत्तम व समाधानकारक आहे. आर्थिक शिस्तीत महाराष्ट्राचा आदर्श इतर राज्यांनी घ्यायला हवा, असे प्रशस्तिपत्रकही त्यांनी दिले.

Sakal	Need more 50 Thousand Cr. for Mumbai's Infrastructure Development – State asked to the Finance Commission

सकाळ

20 SEP 2018

PIB MUMBAI

मुंबई परिसराच्या विकासासाठी हवेत ५० हजार कोटी

वित्त आयोगाकडे राज्याची मागणी

सकाळ न्यूज नेटवर्क

मुंबई, ता. १९ : राज्याच्या गरजा आणि राज्याची विकास क्षेत्रे याबाबत पंधराव्या वित्त आयोगासमोर सादरीकरण करताना सरकारने राज्याला नियमित स्वरूपात प्राप्त होणाऱ्या तरतुदींव्यतिरिक्त मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राच्या (एमएमआर) विकासासाठी ५० हजार कोटी तर विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या समतोल सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी २५ हजार कोटी रुपयांच्या विशेष साह्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

राज्याने नेहमीच देशाच्या आर्थिक विकासात भरीव योगदान दिल्याचे सांगून ते म्हणाले, "सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा हिस्सा १५ टक्के, तर देशाच्या एकूण निर्यातीत महाराष्ट्राचा हिस्सा २० टक्के आहे. भारतात येणाऱ्या थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी ३१ टक्के गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात येते. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक औद्योगीकरण झालेले पान ४ वर »

लोंढ्यांमुळे मुंबईला विशेष मदत

मुंबईत परप्रांतियांच्या अविरत लोंढ्यांमुळे निर्माण झालेल्या समस्या, अडचणींची अधिकृत दखल १५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह यांनी बुधवारी मुंबई दौऱ्यात घेतली. या लोंढ्यांमुळे पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण लक्षात घेता मुंबईसाठी केंद्राच्या योजनांतून विशेष मदत देण्याचा विचार करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती इतर राज्यांच्या तुलनेत उत्तम व समाधानकारक आहे. आर्थिक शिस्तीत महाराष्ट्राचा आदर्श इतर राज्यांनी घ्यायला हवा, असे प्रशस्तिपत्रकही त्यांनी दिले.

Sakal	Need more 50 Thousand Cr. for Mumbai's Infrastructure Development – State asked to the Finance Commission

पुढारी

20 SEP 2018

PIB MUMBAI

धरण पुनर्वसन; सुधारित खर्चाला मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; ३४६६ कोटी खर्च अपेक्षित

नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा

धरण पुनर्वसन आणि सुधारणा प्रकल्पाच्या (डीआरआयपी) सुधारित खर्चाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. दरम्यान, अंगणवाडी सेविका आणि अंगणवाडी मदतनीसांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्याच्या प्रस्तावावरही या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

योजनेसाठी याआधी २१०० कोटी रुपयांचा खर्च गृहीत धरण्यात आला होता. सुधारित अंदाजानुसार डीआरआयपी प्रकल्पांसाठी ३४६६ कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून, यातील जागतिक बँकेची हिस्सेदारी २६२८ कोटी रुपयांची राहील, असे कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

देशभरातील १९८ धरणांची सुरक्षितता तसेच त्यांच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी डीआरआयपी योजना राबविण्यात येते. योजनेसाठी जागतिक बँककडून निधी प्राप्त होतो तसेच राज्यांना काही प्रमाणात निधीची तरतूद करावी लागते. ३० जून २०२० पर्यंत डीआरआयपी योजनेसाठी ३४६६ कोटी रुपये खर्च करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्राने आज मंजुरी दिली. धरणक्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांची जीवित तसेच वित्तहानी होऊ नये, यासाठी विविध प्रकारच्या योजना डीआरआयपीअंतर्गत राबविण्यात येतात.

अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांच्या मानधनात वाढ...

अंगणवाडी सेविका आणि अंगणवाडी मदतनीसांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केला होता. या निर्णयावर आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. अंगणवाडी सेविकांना आता ३ हजार रुपयांच्या ऐवजी ४५०० रुपये इतके मासिक मानधन मिळणार असून, मिनी अंगणवाडी केंद्रातील सेविकांना २२५० रुपयांऐवजी ३५०० रुपये, तर अंगणवाडी मदतनीसांना १५०० रुपयांऐवजी २२५० रुपये इतके मानधन मिळणार आहे. देशभरातील २७ लाख अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना मानधन वाढीचा फायदा होईल, असे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.

Pudhari	Dam Rehabilitation; Revised Expenditure approved

ગુજરાત સમાચાર

20 SEP 2018

PIB MUMBAI

મહારાષ્ટ્રની આર્થિક સ્થિતિ બહેતર ૧૫મા નાણા પંચનો અભિપ્રાય

(વિશેષ પ્રતિનિધિ) મુંબઇ, તા.૧૯

મહારાષ્ટ્રની અર્થવ્યવસ્થાના દ્રષ્ટિથી રાજ્ય સરકાર તરફથી જરૂરીએ ડ્રાફ્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ ડ્રાફ્ટ મુજબ મહારાષ્ટ્રમાં અર્થ વ્યવસ્થા ત્રણ ટ્રિલીયન ડોલર જેટલી થશે, એવા શબ્દોમાં ૧૫મા ફાઇનાન્સ કમિશને ફડણવીસ સરકારને સર્ટિફિકેટ આપ્યું છે. મહારાષ્ટ્રની અર્થવ્યવસ્થા માટે વ્યક્ત કરવામાં આવેલી ચિંતા આ રાજ્યની પ્રતિમા મલિન કરવાના હેતુથી નહીં હતી એવી સ્પષ્ટતા ફાઇનાન્સ કમિશનના અધ્યક્ષ એન.કે. સિંહેએ કરી.

છેલ્લા ત્રણ દિવસથી રાજ્યની અર્થવ્યવસ્થા પ્રત્યે જાણકારી લઇને આ અર્થ વ્યવસ્થા રાજ્યને સક્ષમ બનાવવાના દ્રષ્ટીથી શું કરવું જોઇએ એની ચર્ચા કરવા માટે ૧૫મા ફાઇનાન્સ કમિશને મહારાષ્ટ્રની મુલાકાત લીધી. શરૂઆતમાં રાજ્યમાં નાણાંકિય પરિસ્થિતિ અંગે કમિશને ચિંતા વ્યક્ત કરતા વિપક્ષોએ ટીકાસ્ત્ર ચલાવીને રાજ્ય સરકારને આરોપીના પિંજરામાં ઉભા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.

બીજી તરફ મુખ્ય પ્રધાન દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને નાણા પ્રધાન સુધીર મુનગંટીવારે તાત્કાલિક બેઠક બોલાવીને રાજ્યના સંબોધન અધિકારીઓને સાણસામાં લઇને રાજ્યની સક્ષમ અર્થવ્યવસ્થા માટે જે પગલા સરકારે ઉઠાવ્યા છે. એ પ્રત્યે ફાઇનાન્સ કમિશનને વાકેફ કરવાની સૂચના કરી. આખરે સંબંધિત અધિકારીઓએ કમિશનને ડ્રાફ્ટ રજૂ કર્યો. ત્યારબાદ કમિશનના અધ્યક્ષ એનકે સિંહેએ પત્રકાર પરિષદ બોલાવીને મહારાષ્ટ્રની ડેવલપમેન્ટ અન્ય રાજ્યોની સરખામણીમાં વિશેખ એટલે ગુજરાત, કર્ણાટક અને તામિલનાડુની સરખામણીમાં સારી થઇ છે. દેશની આર્થિક પરિસ્થિતિમાં મહારાષ્ટ્રની નાણાંકિય પરિસ્થિતિ સારી છે. મહારાષ્ટ્રની ભૂમિકા પણ સારી છે. વિદર્ભ અને મરાઠવાડા તરફ વધુ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે એમ સ્પષ્ટ કર્યું.

Gujarat Samachar (Gujarati)	Finance commission now praises Maharashtra's economy.

સંદેશ

20 SEP 2018

PIB MUMBAI

PRESS INFORMATION BUREAU LIBRARY MUMBAI

મુંબઈના નાણાપંચ પાસેથી માગવામાં આવશે સ્પેશિયલ ભંડોળ

રાજ્યની આર્થિક સ્થિતિ બિલકુલ ખરાબ નથી થઈ: મુનગંટીવાર

નાણાપંચના અહેવાલ બાદ વિપક્ષે સરકારને નિશાન બનાવી હતી

। મુંબઈ ।

રાજ્યના નાણાપ્રધાન સુધીર મુનગંટીવારે કહ્યું હતું કે રાજ્યની આર્થિક સ્થિતિ બિલકુલ ખરાબ નથી થઈ. હદની બહાર કર્જ લેવામાં આવ્યું હોય કે પછી ઓવરડ્રાફ્ટ થાય ત્યારે આર્થિક સ્થિતિ ડામાડોળ થતી હોય છે. પણ એવું કાંઇ પણ નથી થયું. વિપક્ષને નાણા પંચના અહેવાલમાં અમુક બાબતોને જોઈને ખુશ થવાની તક મળી છે, એમાં કોઈ વાંધો નથી. તેમણે કહ્યું હતું કે મુંબઈમાં દેશભરમાંથી લોકો આવતા હોય છે. મુંબઈના વિકાસ માટે અમે રૂ. ૫૦ હજાર કરોડ સ્પેશિયલ ભંડોળનું રૂપમાં માગીશું. મંત્રાલયમાં મીડિયા સાથે વાત કરતાં સુધીર મુનગંટીવારે ઉક્ત વાત કહી હતી.

૧૫મા નાણાપંચના અધ્યક્ષ એન. કે. સિંહ અને અન્ય સભ્ય હાલમાં મહારાષ્ટ્રની મુલાકાત પર આવ્યા છે. નાણાપંચે હાલમાં જ એક અહેવાલ બહાર પાડ્યો છે, જેમાં મહારાષ્ટ્રની આર્થિક સ્થિતિને લઈને પ્રતિકૂળ ટિપ્પણી કરવામાં આવી છે. આ મુદ્દે વિપક્ષે સરકારને નિશાન પર લીધી હતી. નાણાપંચે રજૂ કરેલા અહેવાલની પાર્શ્વભૂમિ પર મુનગંટીવારે કહ્યું હતું કે ઇકોનોમીના માપદંડ અનુસાર સરકાર વેતન આપે છે, કર્જ પર વ્યાજ, પેન્શન આપે છે. આ વાતો સહિત બીજા અનેક મુદ્દાઓને અમે ૧૫મા નાણાપંચની સમક્ષ રાખીશું. ત્યાર પછી નાણાપંચ પોતાના નિષ્કર્ષનો નિશ્ચિત રૂપે ખુલાસો કરશે. મહારાષ્ટ્ર પ્રદેશ કોંગ્રેસ કમિટીએ પણ ૧૫મા નાણાપંચને બુનિયાદી માળખાના વિકાસ માટે મુંબઈને વિશેષ અનુદાન આપવાનો આગ્રહ કર્યો છે.

Sandesh (Gujarati)	The financial condition of the state is not bad: Sudhir Mungantiwar. Mungantiwar Demand For Mumbai Special Fund From Finance Commission